

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को फंसाया जा रहा

988 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ईडी ने पेश की चार्जशीट

राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोकने की भाजपा ने 4 साल पहले ही कोशिश शुरू कर दी है। 2029 के आम चुनावों से पहले ईडी या दूसरी एजेंसियों के माफ़त राहुल गांधी को घेरना चाहती है। जिस कंपनी एजेंसल का अधिग्रहण किया है उसमें 76 प्रतिशत हिस्सा सोनिया राहुल का है।



2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दर्ज किया था कि कांग्रेस नेताओं ने एजेंसल का अधिग्रहण वाईआईएल से किया। इसमें नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार है। इसकी स्थापना 1938 में पं. जवाहर लाल नेहरू एवं कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर की थी। इसका स्वामित्व एजेंसल के पास था। एजेंसल ने कर्ज क्यों लिया। एजेंसल 2008 तक मात्र 90 करोड़ का कर्ज था। इसका प्रकाशन बंद हो गया था। कांग्रेस मात्र 90 करोड़ की राशि एजेंसल ग्रुप के रूप में दी थी। इस प्रकार निजी शिकायत पर पहली बार ईडी जांच कर रही है। अब तक सरकारी शिकायतों पर ही ईडी जांच करती आई थी। अभी हाल ही में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी निजी शिकायत के आधार पर जांच की गई थी।



रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा

एक ओर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजमाता एवं प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ईडी, एफआईआर दर्ज करा रही है तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के जवाई रॉबर्ट वाड्रा को बुधवार को दूसरे दिन ईडी ने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया। रायबरेली से सांसद व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दरवाजा तक छोड़ने आईं। जिससे उनका मनोबल बना रहा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यदि ईडी परेशान करेगी तो और स्ट्रांग बनेंगी। जब तक ईडी गुरुग्राम जमीन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करती रही। तब तक प्रियंका वाड्रा वॉटिंग रूम में बैठी रही। बयान पूरे होने पर रॉबर्ट वाड्रा को अपने साथ लेकर गईं। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी मुझे व राहुल गांधी को संसद में जाने से रोकना चाहती है और मुझे बाहर रोकना चाहती है। लेकिन हम डरते नहीं। इस मामले में वाड्रा मुख्य आरोपी है, उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी थे।

कांग्रेस आजकल आंतरिक मतभेदों में उलझी

हाईकमान से लेकर प्रदेश स्तर की कांग्रेस की राजनीति आजकल आंतरिक मतभेदों में उलझी हुई है। कांग्रेस ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में महाअधिवेशन आयोजित किया लेकिन वह भी लक्ष्य से भटक गया। राहुल गांधी अधिवेशन के बीच में ही राजस्थान के रणथंभौर में बाघों की चहलकदमी देखने पहुंच गए। राजस्थान की कांग्रेस भी जूली और गोविन्द सिंह डोटसरा के बीच बंटी हुई है। राहुल गांधी सचिन पायलट को आगे लाना चाहते हैं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीच-बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। वे अपनी लॉबी को आगे लाना चाहते हैं। आपसी संघर्ष में प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी का छापा पड़ गया लेकिन कोई बड़ा नेता खाचरियावास के पक्ष में सामने नहीं आया।

कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात के बजाय बिहार में होना चाहिए था

कांग्रेस ने गुजरात में कांग्रेस की वापसी के लिए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में अधिवेशन किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरदार पटेल तो पहले ही कांग्रेस के थे। अब भी कांग्रेस के ही हैं। भाजपा कितना भी जोर लगा लें लेकिन सरदार पटेल को कांग्रेस से नहीं छीन सकती। बिहार में अधिवेशन होता तो नीतीश बाबू के खेमे में हलचल होती। कांग्रेस को फायदा होता। मजबूरी में बेचारे तेजस्वी यादव को दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिलना पड़ा। अभी 2029 दूर है। भाजपा विपक्ष को समाप्त करने में लगी है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निपटकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। ईडी की अभी शुरुआत है न जाने कितने नेताओं पर ईडी की मार पड़ने वाली है। यह तो भविष्य ही बताएगा। कांग्रेस के लिए इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है।

जयपुर आ सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

आमेर और जंतर-मंतर घूमने जा सकते हैं;

एयरपोर्ट पर उतरे अमेरिकी

एयरफोर्स के बड़े विमान

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत दौरे (21 से 24 अप्रैल) के दौरान जयपुर भी आ सकते हैं। उनकी विजिट को लेकर जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बढ़ गया है। जयपुर के

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के दो विमानों की लैंडिंग हुई है।

सूत्रों के अनुसार, वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। सी - 17 ग्लोबमास्टर दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी के साथ इंडियन आर्मी भी करती है। मंगलवार-बुधवार को ऐसे ही दो विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे।

भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेषाधिकारियों की होगी नियुक्ति

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल



उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के

20 अप्रैल को होगी बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजेज में भूमि अवाप्ति के अवाई, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्यों में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक हो चुकी

प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित का कार्य शीघ्र करें

शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी पर बने हुए चार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित कर कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि चूरू, जैसलमेर और बीकानेर जिले में पेयजल उपलब्धता में अभिवृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की समीक्षा करते हुए कहा कि फव्वारा सिंचाई पद्धति को विशेष रूप से विकसित किया जाए।

शर्मा ने कहा कि परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन वितरण प्रणाली से लेकर डिग्री एवं पंप हाउस कार्यों में गति लाई जाए। साथ ही, उन्होंने निर्देश

दिए कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं ईसरदा पेयजल परियोजना को जून में पूरा करने के निर्देश दिए। कालोतीर लिफ्ट परियोजना के डिग्री निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा एवं इन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को सहानुभूति के साथ पुनर्वास एवं उचित मुआवजे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना, पीपलखुंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, सावरमती बेसिन के अवर्तन जल एवं देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 प्रकरणों में अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में भी अवाप्ति की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इस परियोजना में बांध निर्माण मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई

देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस, 7 महीने का कार्यकाल; 14 मई से संभालेंगे काम

राजस्थान की राजनीति

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूपेण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोपरावाही और विभागीय जांच के 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोटे हुए थे। उनके



जस्टिस गवई ने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया

जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भीरसे के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोटे हुए। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के परमार्नेट जज बने।

रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है।

वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केंद्र सरकार से पूछा- क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है।



सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा

आरयूएचएस हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक को हटाय

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (आरयूएचएस) हॉस्पिटल में नियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. महेन्द्र कुमार बैनाड़ा को सरकार ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. महेश मंगल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉ. जितेन्द्र पंडा को पद से निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही और विभागीय जांच के चलते दोनों पर ये कार्रवाई की गई है।

ट्रंप ने चीन पर फिर फोड़ा 'टैरिफ बम', बढ़ाकर किया 245 प्रतिशत

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच 'टैरिफ वॉर' में समय-समय पर नए-नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच टैरिफ की यह जंग भी काफी गंभीर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 75 देशों को इस टैरिफ से राहत देने हुए इस पर 90 दिन की रोक लगाते हुए सिर्फ 10 प्रतिशत का रेंसिप्रोकल टैरिफ ही लागू किया है, पर चीन को कोई राहत नहीं दी। ट्रंप ने चीन पर ही सबसे पहले टैरिफ लगाया था और समय के साथ ही इसमें इजाफा करने से भी पीछे नहीं हट रहे। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145 प्रतिशत किया था। अब एक बार फिर ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर 'टैरिफ बम' फोड़ दिया है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 245 प्रतिशत तक करने का फैसला लिया है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। चीन के अपनी एयरलाइन्स को बोइंग जेट्स खरीदने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने के फैसला लिया है। ट्रंप के इस कदम में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ना तय है। चीन लगातार अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है।

राजस्थान में भीषण गर्मी



जैसलमेर में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान 46 डिग्री के पार

जयपुर। राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर बुधवार को भी जारी रहा। जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो जिले का पिछले 6 साल में अप्रैल का सर्वाधिक तापमान रहा। फलोदी, बीकानेर और गंगानगर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल को लू का चार जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने और थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई है। इसमें आंधी चलने, बादल छाने और बारिश होने की गतिविधियां शामिल हैं। बुधवार को जैसलमेर में तेज गर्मी के कारण पारा मंगलवार के मुकाबले एक डिग्री सेल्सियस कम गया। मौसम विज्ञान केन्द्र ने जैसलमेर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। यहां बुधवार को अधिकतम तापमान औसत से 6.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 44.8, गंगानगर में 44.3, बीकानेर में 44.2, जोधपुर में 43.2, जालौर में 42.3, पिलानी में 41.6, सिरौली में 41.3, पाली में 41.7 और भीलवाड़ा में तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

बच्चे को मुंह में दबोचकर ले गया टाइगर

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया- वे दोपहर 3 बजे गणेशजी के दर्शन करके वापस लौट रहा था। उसके साथ एक महिला अपने 7 साल के पोते के साथ आ रही थी। अचानक जंगल से निकलकर एक टाइगर बाहर आया और बच्चे को मुंह में दबोचकर ले गया। घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई।

इलाके में था टाइगर टी-120 का मूवमेंट

जावकारी के अनुसार, जिस इलाके में बच्चे पर टाइगर ने हमला किया है, वहां पिछले दो दिनों से टाइगर टी-120 का मूवमेंट था। ऐसे में आश्चर्य जताई जा रही है कि बच्चे पर हमला टाइगर टी-120 ने किया होगा।

मंदिर ट्रस्ट ने दी 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट की ओर से मृतक के परिवार को डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के प्रधान सेवक जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी पहुंचे और परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की।



गोहटा थाना देई खेड़ा (बूंदी) के रूप में हुई है। उधर, बच्चे पर हमले की घटना के बाद वन विभाग ने रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पांच दिन के लिए रोक लगा दी है। मुख्य वन संरक्षक ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले पैदल रास्ते में बाघ का मूवमेंट होने की बात कही है।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के 280 बीएलए शामिल



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भूमिका और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार वृद्धिहित मतदाता सूचीयां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई।

राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी 28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अधिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

गुरूवार को आयोजित होगा जिलास्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम

कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी जनसुनवाई

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए 17 अप्रैल, 2025 (गुरुवार) को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। जिलास्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव भी जुड़ेंगे। जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। जिलास्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस करेंगे। इससे पहले गुरुवार को ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक प्रातः 10:30 बजे आयोजित की जायेगी। बैठक में समिति में दर्ज प्रकरणों पर गहनता से चर्चा की जायेगी।

राज्यपाल बागडे से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की शिष्टाचार भेंट



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से बुधवार को राजभवन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुलाकात की । इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

पुरालेखाण (राजस्थान राज्य अभिलेखागार) प्रतियोगी परीक्षा-2024 3 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 3 अगस्त 2024 को आयोजित पुरालेखाण (राजस्थान राज्य अभिलेखागार) प्रतियोगी परीक्षा-2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों की मुख्य सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा अंतर्गत पात्रता जांच हेतु विचारित सूची 14 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। इस सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच उपरांत 3 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।

सीएम के बाद दौसा विधायक को मिली धमकी, सुरक्षा बढ़ाने को लेकर एसपी से मिले विधायक

विधायक को जान से मारने व गाली

गलौज करने का ऑडियो सोशल

मीडिया पर हो रहा है वायरल

राजस्थान की राजनीति

दौसा (विष्णु आशीर्वाद)। राजस्थान के अंदर धमकी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है बात कर रहे हैं दौसा जिले की दौसा जिले से पूर्व में श्यालावास जेल से सीएम भजनलाल को दो बार धमकी मिल चुकी है और वर्तमान कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा को बीती रात सोशल मिडिया पर धमकी मिली है जिसको लेकर आज विधायक डीसी बैरवा ने दौसा एसपी से मिले और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा को सोशल मीडिया पर लगातार धमकिया मिल रही है। इसी को लेकर बुधवार को विधायक दीनदयाल बैरवा एसपी सागर राणा से मुलाकात करने एसपी कार्यालय पहुंचे और लगातार मिल रही धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस अवसर पर एसपी से सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है मेरी बेटी के बारे में भी गालियां दी गई है इस मामले को लेकर हम एसपी कार्यालय आए हैं और एसपी से शिकायत

नई शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और चुनौतियों से जूझने की शिक्षा देने वाली, विकसित भारत के अंतर्गत मन, आचार, विचार भी विकसित होंगे —राज्यपाल

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में शिक्षा में जो बजट आवंटित किया है वह विद्यार्थियों के विकास के लिए है। शिक्षा से विद्यार्थी का मन विकसित होता है तो अपने आप ही आपदाओं से जूझने के लिए समाज तैयार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत मन, आचार, विचार भी विकसित होंगे। राज्यपाल ने विनोबा भावे के कथन की चर्चा करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ और देश का झंडा बदला गया तभी शिक्षा नीति भी बनानी चाहिए थी। मगर यह बदली नहीं, इसलिए विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से और विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। राज्यपाल बागडे बुधवार को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा अभियान) के अंतर्गत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, सेवा भारती और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ःमानव जोड़े आदमी जोड़े- की शिक्षा दी है। इस शिक्षा का अर्थ है, मन से लोगों से संबंध बनाए। देश प्रेम से युवा पीढ़ी जुड़े। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता बढ़े। इसलिए आदमी जोड़ने का कार्य हो। आदमी जोड़ने का अर्थ है, भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। उन्होंने नकल मुक्त शिक्षा पर



की है। इस प्रकार की धमकियां मुझे पहले भी मिल चुकी है और हाल ही में मुझे कल एक ऑडियो आया है। मेरी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो ऐसी कोई चीज पब्लिक में नहीं जाए इस मामलों को लेकर मैं ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन इस मामले में मैंने पहले प्रशासन को ही अवगत करा दिया था। इस तरह की धमकी मुझे कई बार मिलती रहती है। कल ऑडियो वायरल होने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई है। गाली गलौज की गई है फिर उसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिसका मेरे कार्यकर्ताओं में दुख है मुझे भी खुद को भी दुख है अभी तो मैंने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा गया है और कर दिया। मैं एसपी

सागर राणा से मुलाकात का पूरा घटनाक्रम बताकर आया हूं मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले को लेकर एसपी सख्त कदम उठाएंगे। मीडिया द्वारा सुरक्षा मांगने के सवाल पर कहा कि मैं सुरक्षा को लेकर पूर्व एसपी को भी लिखित में पत्र दिया था और इन मौजूदा एसपी सागर राणा को भी अवगत कराया कि आए दिन मुझे धमकी मिल रही है इस लिए मेरी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मेरी जान को खतरा तो है इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।



जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तभी यह संभव हो सकेगा। उन्होंने रटने की बजाय मन से पढ़ने, पढ़ाने लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वही ज्ञान सार्थक है जो समय के साथ प्रासंगिक रहे। नई शिक्षा नीति इसी आधार पर तैयार की गई है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का वह आलोक है, जिसमें जीवन की तमाम आपदाओं से मुकाबला करने की दृष्टि है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आपदा के बाद पुनर्वास के तरीके भी बताए गए हैं। आरंभ में उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने वाली संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों व स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय ग्रंथों में बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा

में भूस्खलन से बचाव के लिए उचित स्थान पर घर बनाना, बाढ़ से बचाव के लिए बांध और नहरें बनाना, और सूखा से बचाव के लिए पानी का संरक्षण की परंपराएं हमारे यहां आपदा प्रबंधन रूप में ही बनीं। उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले ने मुख्य वक्ता के रूप में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देश में समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में आपदा से बचाव के लिए मन से विद्यार्थी तैयार किए जाने पर जोर दिया। आरंभ में कॉलेज शिक्षा सचिव भानु प्रकाश अटरू, आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने राजस्थान में कॉलेज शिक्षा की प्रगति और नई शिक्षा नीति, ज्ञान परम्परा और आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी।

विधायिका के प्रति बढ़ी कार्यपालिका की जवाबदेही - विधानसभा अध्यक्ष

देश की एजेंसियों पर सवाल

उठाना संविधान की मूल भावना

के विरुद्ध - विधानसभा अध्यक्ष

ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता को

किया सम्बोधित

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधायिका के प्रति राज्य की कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। विधानसभा में 10 हजार से अधिक लिखित प्रश्नों में से 95 प्रतिशत के जवाब आए हैं। इनमें लगभग साढ़े चार हजार प्रश्न तो 15वीं विधानसभा की भी लिखित थे। इससे लोकतंत्र व जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की संकल्पना मजबूत हुई है। पहली बार विधानसभा में पेपरलेस कार्रवाई, विधायकों के लिए आइपेड उपलब्ध करवाने सहित कई नवाचार किए गए हैं। यह



पर्यावरण के लिए भी लाभदायी है और गुड गवर्नेंस के लिए भी।

उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप का शौर्य, आदिवासी संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों कलाकृतियों को विधानसभा की दर्शक दीर्घा में संजोया गया है। इससे नई पीढ़ी को हमारी अनमोल धरोहर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। देवनानी ने बुधवार को उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गुलाबी रंग से

परिवेश बेहतर बना है। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा और समाजसेवी गजपाल सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे।

संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित

देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि यदि केंद्र सरकार बहुमत के साथ किसी बिल को पास करती है तो उसे सभी राज्यों को

मानना पड़ता है। यह संघीय ढांचे का आधार है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की स्वायत्ता पर सवाल उठाना देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, इसके बावजूद इस पर सवाल उठाना संविधान की मूल भावना पर सवाल उठाने के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों को देश की सर्वोच्च अदालत और संवैधानिक सदनों पर विश्वास रखना चाहिए।

विदेशों में भारत का मान बढ़ा

देवनानी ने कहा कि आज वैश्विक परिदृश्य में भारत एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों को छू रहा है। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो नेशन फर्स्ट का भाव रखें।

व्यावहारिक तौर पर राजस्व आधारित मॉडल हो विकसित- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी

जेकेके में विभिन्न प्रदर्शन स्थानों पर लगे वयूआर कोड



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष जवाहर कला केन्द्र के लिए की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बुधवार को पर्यटन भवन में शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा जेकेके महानिदेशक रवि जैन की वीसी द्वारा उपस्थिति में जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जेकेके हेतु आवंटित बजट राशि 8 करोड़ का रचनात्मक विकास कार्य करवाये जाने के निर्देश देने के साथ ही जेकेके संचालन के लिए कला और कलाकार का संरक्षण करने हेतु व्यावहारिक तौर पर राजस्व आधारित मॉडल विकसित किए जाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कला और क्राफ्ट संरक्षित और विकसित करने हेतु सकल्पित है। कला और कलाकारों को नियमित मंच उपलब्ध हो तो कलाएं और क्राफ्ट जीवित और संरक्षित रहेंगे। उन्होंने जेकेके में विभिन्न प्रदर्शन स्थानों पर आने वालों को उस स्थान की विस्तृत जानकारी देने के लिए व्यूआर कोड लगाये जाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने जेकेके के डेटा को डिजिटाइज किये जाने, दैनिक होने वाले आयोजनों की आमजन को जानकारी देने के लिए हर बार लगाये जाने वाले होर्डिंग्स के स्थान पर होर्डिंग एलइडी लगवाए जाने, लाइब्रेरी का विकास करने, शिल्प ग्राम में राज्य भर के बेस्ट कला उत्पादों के विक्री प्रदर्शन किये जाने के लिए आर्टिजन्स को नियमित अवसर दिए जाने के निर्देश दिए।

सौर ऊर्जा अपनाओ— बिजली का खर्चा बचाओ

उपमुख्यमंत्री ने जेकेके में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से बिजली का खर्चा बचेगा।

जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती अलका मीणा द्वारा आईटी और टेक्निकल कार्य के साथ सिविल कार्य करवाये जाने हेतु विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक ली— राजस्थान उच्च शिक्षा में बेहतर बने —राज्यपाल



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नवाचार अपनाते हुए नवीन उपकरणों के आविष्कार में भारत को अग्रणी बनाने, अधिक से अधिक पेटेंट स्वीकृत करवाने, पाठ्यक्रमों में बौद्धिक क्षमता विकास के लिए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। बागडे बुधवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने और 'नैक' एकीकरण के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी ली तथा कहा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान उच्च शिक्षा में बेहतर बने, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए यदि नियमों में और कानून में बदलाव की भी आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय ज्ञान परम्परा और संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन अध्यापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने 'नैक' के मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिस्वीकृत करवाने के लिए कार्यवाही समयबद्ध करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप भारत वैश्विक स्तर पर ज्ञान संपन्न बने, इसके लिए सभी कार्य करें। उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों को देशभर में अग्रणी किए जाने का भी आह्वान किया।

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने राजस्थान में विश्वविद्यालयों में नवाचारों के साथ वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता जाहें। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भानु प्रकाश अटरू ने राजस्थान में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित प्रगति के बारे में अवगत कराया।

बजट घोषणाओं एवं रात्रि विश्राम की समीक्षा बैठक

बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें- पंचायती राज मंत्री



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 को विभागीय बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्य में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। दिलावर बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यों के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के रात्रि विश्राम के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करें। उन्होंने स्वाभिम्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंभीरी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिस्टमोरिटी (एफईएस) के साथ वनस्पति सीड बैंक के संबंध में एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में बैठक में डॉ. जोगाराम शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुहम्मद जुनैद, निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, श्रीमती सरोजोी खेमका, निदेशक स्वेच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।



राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का कर्े व्यापक प्रचार-प्रसार, योजना के अंतर्गत शत—प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर पूरे मनोयोग से करे प्रयास, ब्याज अनुदान योजना में 95 प्रतिशत से कम वसूली वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को दो नोटिस — प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं। राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शुरुआत से ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियावित्त करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए। बैठक में भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियावित्तिके लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। वहीं, भूमि विकास बैंकों में भर्ती के बिन्दु पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाए। साथ ही, कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है। राजपाल ने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति एवं एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधिपार ऋण मामलों एवं नियमित मामलों में वसूली कार्यक्रम पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रहा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए भत्व संग्रहालय संरक्षण विकास कार्यों का हो अनुसरण- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की उपस्थिति में बुधवार को पर्यटन भवन में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, माउन्ट आबू और आहाड़ के संग्रहालयों के संरक्षण हेतु विकास कार्य करवाये जाने के लिए प्रस्तुतिकरण दिया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संग्रहालयों में बेशकीमती कलाकृतियाँ हैं। इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस हेतु कलाकृतियों का डिजिटल डेटा तैयार किये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संग्रहालयों में कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञों की टीम बनाकर उनकी राय के आधार पर संग्रहालय संरक्षण के विकास कार्य करवायें जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बिना सोचे समझें अन्यव्यहारिक रेनोवेशन नहीं किया जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संग्रहालयों के संरक्षण के विजन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात और दिल्ली में संग्रहालयों के संरक्षण के भव्य विकास कार्य करवाये हैं जो कि अनुकरणीय है। इसी तर्ज पर राजस्थान में भी संग्रहालय संरक्षण के कार्य किये जाने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक रूप से राजस्थान के 5-7 आइकॉनिक म्यूजियम के रेनोवेशन के लिए केन्द्र सरकार को ग्रांट हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने संग्रहालय पर साइनेज, शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। प्रस्तुतिकरण में उक्त संग्रहालयों के नवीनीकरण का कार्य 35 साल बाद प्रस्तावित होना बताया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया गया।

‘मंत्री आपके द्वार’ के तहत गांव-गांव पहुंचे कृषि मंत्री, शेरपुर, उलियाना एवं चकेरी गांवों में की जनसुनवाई, टाड़गर हमले में मृतक की पत्नी को दी 5 लाख की आर्थिक सहायता

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को ‘मंत्री आपके द्वार’ जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत सवाईमाधोपुर जिले के शेरपुर, उलियाना एवं चकेरी गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की कृषि, उद्यानिकी, विद्युत, शिक्षा सहित अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए आमजन को अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जनसुनवाई के दौरान कृषि मंत्री ने गर्मी के मौसम में किसी भी गांव को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए विधायक कोष से विभिन्न स्थानों पर बोरिंग, हंडेपंप लगवाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने चकेरी गांव में 10 लाख रुपये की लागत से इथाई छतरी का निर्माण करवाने, 10 लाख रुपये की लागत से सड़कों की मरम्मत करवाने की घोषणा भी की। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन करवाने, ग्राम पंचायत खिलचीपुर में लाईबेरी खुलवाने, आम रास्तों से अतिक्रमण हटवाने, ट्रांसफार्मर लगवाने, विद्युत कनेक्शन करवाने, झरेटी नाले पर छोटी लाईन को बड़ी करवाने, मकान की छत से गुजर रही विद्युत लाईन को शिफ्ट करवाने, मुख्य सड़कों एवं खेत के बीच से विद्युत पोल हटवाने, बिजली बिलों की त्रुटियों का समाधान करवाने, बैरवा बस्ती में पानी समस्या का समाधान करवाने, गौशाला हेतु भूमि आवंटन करवाने सहित अनेक प्रकरण प्राप्त हुए। उन्होंने सभी प्रकरणों पर शीघ्र



कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान कृषि मंत्री के विशेष प्रयासों से सवाईमाधोपुर जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 400 केवी जीएसएस एवं 132 केवी जीएसएस स्वीकृत करवाने के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों ने मंत्री का आभार जताया और उनका अभिनंदन किया।

उलियाना में स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालय का किया लोकार्पण, पद दंगल में हुए शामिल

मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ग्राम उलियाना में 1 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उलियाना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच गाँव-गाँव तक सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नव स्थापित स्वास्थ्य केंद्र से क्षेत्र के नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने से जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

अतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ, अधिकारी फ़ील्ड विजिट कर सुनिश्चित करें प्रभावी क्रियान्वयन

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत नए लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सब्सिडी धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वचिंतों को उनका हक दिलाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार फ़ील्ड विजिट कर योजनाओं की प्रगति के बारे में फ़ीडबैक लें। जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने ताकि वे समुचित लाभ ले सकें। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

गिव अप अभियान के तहत 17.52 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, 324 करोड़ रु. की हो रही बचत

गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए गत वर्ष शुरु किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का उपयोग नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोदारा ने कहा कि एनएफएसए से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेगे। इससे राज्य सरकार को होने वाली बचत का भी उपयोग वास्तविक हकदारों के कल्याण हेतु किया जा सकेगा। उन्होंने स्वतन्त्र खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये तथा कहा कि राशन वितरण में अनियमिता बरतने वाले राशन डीलरों पर विभागीय अधिकारी उचित कार्रवाई करें।



राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की ई— केवाईसी प्रक्रिया करवाई गई प्रभावी रूप से संपन्न

गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी हेतु लाभार्थियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया संपन्न करवा ली गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 10 वर्ष आयु तक के एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को ई-केवाईसी की बाध्यता से मुक्त रखने का संवेदनशील निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जिन लाभार्थियों ने गत 31 मार्च तक ई-केवाईसी सम्पन्न नहीं करवाई, उनका नाम भी एनएफएसए से हटाया गया है। ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण 27 लाख से अधिक लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है। इससे बचने वाले अन्न का उपयोग नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़कर लाभान्वित करने में किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए से जोड़ना था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब तक 19.70 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। इसी प्रकार गत वर्ष 12.95 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया था। वर्तमान सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में अब तक लगभग 33 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। साथ ही इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर तथा मां योजना के तहत निःशुल्क उपचार से लाभान्वित किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की वंचित वर्गों के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

लौटाए गए आवेदनों के बारे में आवेदकों को मिले उचित सूचना

गोदारा ने कहा कि कई बार समावेशन दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण पात्र लाभार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ने हेतु दिया गया आवेदन लौटा दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में आवेदक

विद्यालय उलियाना का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों और नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा मिले। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधन समिति को इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए बधाई दी और आश्चस्yt किया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस दौरान मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ग्राम पंचायत उलियाना में टाड़गर हमले में मृतक भरत लाल मीणा की आश्रित पत्नी प्रसादी देवी एवं पुत्र विजय मीणा को राहत स्वरूप 5 लाख रुपये की नगद सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान कृषि मंत्री ने ग्राम पंचायत उलियाना में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पद दंगल जैसी सांस्कृतिक परंपराएं हमारी लोकधारा, भक्ति भावना और सामाजिक एकता की प्रतीक हैं।

प्राध्यापक-विद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024, पात्रता जांच हेतु अंग्रेजी तथा व्याकरण विषय की विचारित सूची जारी

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक-विद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के तहत अंग्रेजी एवं व्याकरण विषय के पदों हेतु पात्रता जांच के लिए विचारित सूचियां जारी की गई हैं। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त दोनों विषयों के पदों हेतु प्रश्न पत्र-प्रथम की परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को किया गया था। अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र-द्वितीय की परीक्षा 19 नवंबर 2024 तथा व्याकरण विषय के प्रश्न पत्र-द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर 2024 को किया गया था। परीक्षा के फलस्वरूप अंग्रेजी विषय के 34 तथा व्याकरण विषय के 24 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु विचारित सूची में सम्मिलित किया गया है। विचारित सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन/वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जायेगी। उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्कूटनी- अल्ताई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 (रात्रि 11.59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होंवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों व नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा-2024, आयोग ने जारी किए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विशेष दिशा—निर्देश

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत सामान्य व्याकरण तथा हिंदी विषय की विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के विषय सामान्य व्याकरण तथा हिंदी हेतु दिनांक 9 अप्रैल 2025 को घोषित विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों को निम्नांकित दिशा-निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी— विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्कूटनी- अल्ताई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 (रात्रि 11.59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होंवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

प्राध्यापक एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग), सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर के अतिरिक्त प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 (24 विषय) एवं सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 (33 विषय)का आयोजन 23 जून से 6 जुलाई 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार 17 से 23 अप्रैल 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुसूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया

संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रु. 500/- का शुल्क जमा करना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल <https://rpssc.rajesthan.gov.in> पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन के रूप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmentpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 93523232625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

वांछित अहर्ता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विज्ञ

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है।



बलदेव विधायक ने किया गंगाजल योजना की टंकी का उद्घाटन

जल्द मिलेगा ग्रामीणों को गंगा जल- पूरन



राजस्थान की राजनीति

फरह (डीके)। जलजीवन मिशन के तहत महुअन में निर्माणाधीन दो लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी का बुधवार को विधायक पूरन प्रकाश ने उद्घाटन किया। हवन यज्ञ कर विधिविधान से पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक पूरन प्रकाश ने कहा , हर घर में जल्द गंगाजल पहुंचेगा। अब महिलाओं को पानी के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। इस योजना से कुरकंदा, सनौरा और महुअन को जोड़ा गया है। इस मौके पर जिला माहमंजी किसान मोर्चा सुरेश तवरकर, मंडल अध्यक्ष पारस ठाकुर, राजेन्द्र प्रधान कुरकन्दा, अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार, गौरव कुमार, अनिल रावत, हरिओम प्रधान आदि उपस्थित रहे।

ग्राम प्रधान को कार्यक्रम से तयों दूर रखा

उद्घाटन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत महुअन ने भूमि उपलब्ध कराई, उसी पंचायत के प्रधान को उद्घाटन कार्यक्रम से दूर रखा गया। कार्यक्रम में न तो ग्राम प्रधान जसोदा न ही प्रधान प्रतिनिधि देवेन्द्र सिंह दिखे। पता नहीं कौनसी बेवशी रही होगी। यहां तक कि अन्य पंचायतों के प्रधान मौजूद थे,लेकिन योजना से जुड़े किसी भी ग्राम पंचायत का कोई प्रधान उद्घाटन कार्यक्रम में हिरकत करने नहीं पहुंचा।

मारपीट कर फायरिंग करने का आरोप

उत्तरप्रदेश की राजनीति

केसीकलां/छाता। छाता अपने क्लॉनिक से अपने गांव धर्मसिंगा लौट रहे दो वाइक सवार भाइयों ने तीन नामजदों सहित अज्ञातों पर गाली गलौज कर, मारपीट करने एवं फायरिंग कर घायल करने का आरोप लगाते हुए थाना कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गांव धर्मसिंगा निवासी जयनारायन, देवकीनंदन पुत्रगण डॉ लक्ष्मीचंद गत रात 8 बजे अपने क्लॉनिक बरसाना से वाइक द्वारा गांव लौट रहे थे। आरोप है कि जैसे ही वह दोनो गांव नगला बंजारा के पास आसपास गांव के कुछ लोग पराब पी रहे थे, जिन्होंने उनकी वाइक को रूकवा लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। जान बचाकर भागे वाइक सवारों ने गांव धर्मसिंगा पहुंच कर मामले की जानकारी डायल 112 पर दी। पीडित का आरोप है कि कुछ देर बाद पुलिस ने थाना आने को कहा। जब तक वह थाना पहुंचते इससे पहले ही उक्त नामजदों सहित आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों ने उनके घर पहुंच फायरिंग की, जिसमें जयनारायन, परसराम पुत्रगण डॉ. लक्ष्मीचंद, गोली लगने से घायल हो गए। घायल जयनारायन ने थाना कोतवाली में तहरीर दी है।

अनहोनी की आषंका को देख पुलिस से लगायी गुहार

उत्तरप्रदेश की राजनीति

कोसीकलां। गांव शाहपुर निवासी रामअवतार पुत्र नारायण उपाध्यक्ष बजरंग दल के घर से छाता की ओर लौट रहे बजरंग दल के जिला संयोजक रामतोमर पुत्र किसनदत्त निवासी ऐंच का आरोप है कि रास्ते में समुदाय विषे के दो युवकों ने रास्ते में उसकी गाड़ी रोक ली और विभिन्न धमकियां दीं। इतना ही नहीं उक्त लोगों ने फोन कर अपने करीब छई दर्जन से अधिक अज्ञात हथियारबंद साथियों को मौके पर बुला लिया। लेकिन वह मौका पाकर वहां से भाग निकला। पीडित ने कोई अनहोनी न हो इसके लिए युवक ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए थाना में तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।

फायरिंग के मामले में वांछित एक पकड़ा

उत्तरप्रदेश की राजनीति

कोसीकलां। दुकान पर आकर जान से मारने की धमकी देने एवं फायरिंग करने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी का पुलिस ने चालान कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार निवाँल ने बताया कि मामले में वांछित चल रहे ब्राह्मणपुरी निवासी सोनू को अनाज मंडी के गेट के समीप से हिरासत में लिया है। युवक के कब्जे से तमचा, कारतूस बरामद हुआ है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

नमजदों पर लगाया छेड़छाड़, मारपीट का आरोप

उत्तरप्रदेश की राजनीति

कोसीकलां। गांव बुखारी निवासी एक व्यक्ति ने गांव के आधा दर्जन नामजदों के खिलाफ घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ देने व बच्चों तथा भतीजों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना कोसीकलां में मुकदमा दर्ज कराया है। गांव निवासी व्यक्ति का आरोप है कि गांव के ही राधे, राजेश, नेम सिंह, संतोष, कान्हा सिंह, के द्वारा एक राय होकर उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए विरोध करने पर हमलावरों ने उसके बच्चों व भतीजे के साथ मारपीट की। इस दौरान फिर में चोट आने से उसका भतीजा लोकेश पुत्र क्षेत्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के आ जाने पर हमलावर को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

दो पक्षों में हुई मारपीट

उत्तरप्रदेश की राजनीति

कोसीकलां। गांव लालपुर निवासी कपिल पुत्र तोताराम एवं कपिल पुत्र करनार सिंह, सूरज पुत्र सतबीर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में चले लाठी, डंडों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ रहे लोगों का चालान कर दिया।

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन बोर्ड बैठक, भाजपा पार्षदों ने जताया विरोध एवं बैठक किया बहिष्कार

राजस्थान की राजनीति

मथुरा। बोर्ड बैठक में काफी संख्या में पार्षद पति एवं अन्य बाहरी लोग बोर्ड बैठक के कक्ष में आ गये जिसको लेकर भाजपा पार्षद नीनू कुंज बिहारी भारद्वाज पार्षद वार्ड सं0 56 ने बोर्ड में सर्वप्रथम नगर आयुक्त से प्रश्न किया कि नगर निगम की बैठकों में निर्वाचित पार्षद एवं पदेन सदस्य के अलावा कोई भी अन्य पति अथवा अन्य सम्बन्धियों का बोर्ड बैठक में कोई प्रतिभाग नहीं होना चाहियें। इस सम्बन्ध में पार्षद ने प्रवीर कुमार प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0-3905/नौ-1-12-8 ई/95 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर 2012 का हवाला देते हुये पार्षदों के अलावा अन्य लोगों को सदन से बाहर कराने के लिये नगर आयुक्त से कहा लेकिन नगर आयुक्त ने किसी भी प्रकार का शासनादेश का अनुपालन नहीं किया। भाजपा पार्षद नीनू कुंजबिहारी भारद्वाज बैठक का बहिष्कार कर सदन से बाहर आ गयी।

2. पार्षदों को जो एजेण्डा प्राप्त हुआ है उसके प्रस्ताव सं0 01 में पिछली सम्पन्न हुयी बोर्ड बैठक दिनांक की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में हैं। जिसके बारे में भाजपा पार्षद दल के नेता चौधरी राजवीर सिंह ने बताया कि दिनांक 13



सितम्बर को सम्पन्न हुयी बोर्ड बैठक में जो 15 प्रस्ताव मूल एजेण्डा में थे उसके अलावा जो अन्य अवैध प्रस्ताव बैठक के दौरान ही आनन फानन में लाये गये थे जिसकी शिकायत पार्षदगणों ने लिखित में मण्डलायुक्त आगरा मण्डल आगरा को की थी। जिसके बाद भी मनमानी एवं तानाशाही भ्रष्टाचार के कारण अन्य 14 प्रस्तावों को स्वीकार दिखाया गया हैं। जिसका हम पार्षदगण भारी विरोध करते हैं। इसके महापौर और नगर आयुक्त अन्य पार्षदों को गुमराह करके 14 अन्य अवैध प्रस्तावों को स्वीकार/ पास कराना चाहते हैं। जिसका हम पार्षदगणों ने विरोध किया।

3. बोर्ड बैठक के बारे में जो एजेण्डा मिला व चौकाने वाला ही नहीं अपितु चिन्तन करने वाला भी है। भेजे गये एजेण्डा में महापौर को छोड़कर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि पूर्व में हमेशा नगर आयुक्त,

अपर नगर आयुक्त, सदन प्रभारी एवं महापौर के संयुक्त हस्ताक्षर से एजेण्डा प्राप्त होता रहा हैं। अधिकारियों के एजेण्डा पर हस्ताक्षर न करना अपने आप में एक सदिग्धता प्रदर्शित करता हैं तथा नियम के विरुद्ध भी हैं, जबकि नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता हैं और वह निगम के कामकाज का संचालन करता हैं।

4. एक ही दिन में दो बोर्ड मीटिंग कराना भी सुनियोजित लगता है। लगभग ग्यारह सौ करोड़ का भारी भरकम बजट है। यह बैठक भी इसी दिन दूसरे सत्र में रखी गयी है जिसका समय नाकाफी है। बजट को जानने व प्रश्नकाल हेतु विस्तृत समय की आवश्यकता होती है। साथ ही हम पार्षदगणों ने बजट के लिए मीटिंग हॉल में प्रोजेक्टर लगाकर माननीय सदन को पूरी विस्तृत जानकारी देने के बारे में कहा तथा बजट के लेखा जोखा एवं



खर्चें की बेलेंस शीट के बारे में भी माननीय पार्षदगणों को उपलब्ध कराने के बारे में कहा। लेकिन तानाशाही, मनमानी एवं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अधिकारियों ने हमारी बात को अनसुनी कर दिया।

5.पार्षद बृजेश खरे वार्ड 17 ने आउटसोर्स, डूडा एवं सीएलसी कम्पनी के द्वारा कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने एवं 26 दिन की जगह महीने की अंतिम तारीख तक पूरे महीने का वेतन देने की मांग सदन में रखते हुए काफी पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र नगर आयुक्त को सौंपा, जिसपर नगर आयुक्त ने संतोषजनक जबाब न देते हुए विषय को टाल दिया, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों में भारी आकोश व्याप्त हो गया।

6.हम पार्षदगणों ने दिनांक 27 मार्च को दो शिकायती पत्र कमशः नगर निगम की भूमि पर नगर निगम के अधिकारियों ने गलत तरह से दी गयी

एनओसी एवं नगर निगम की उपविधि के विपरीत पार्किंग के उठये गये ठेके को लेकर लिखित में शिकायतें नगर आयुक्त को कीं।

लेकिन आज तक उक्त शिकायतों को लेकर नगर आयुक्त ने न कोई गम्भीरता दिखाई और न ही संबधित के खिलाफ कोई कार्यवाही की। जिससे प्रतीत होता है कि नगर आयुक्त की भूमिका सदिग्ध है।

6 बिन्दुओं को लेकर भाजपा पार्षदों ने मुखर होकर बोर्ड बैठक में विरोध जताया तथा अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही का विरोध करते हुए भाजपा पार्षदगणों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार करते हुए मीटिंग हॉल से सभी पार्षद बाहर आ गये। बहिष्कार करने वालों में प्रमुख रूप से चौधरी राजवीर सिंह, नीनू कुंजबिहारी भारद्वाज, बृजेश खरे, नीरज वशिष्ठ, ठाकुर तेजवीर सिंह आदि रहे।

सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करे तथा होम विजिट बढ़ाए



उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विभिन्न विभागीय कार्यों ,पोषण अभियान ,पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, हॉट कुक योजना की प्राति सहित सभी विभागीय योजनाओं का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। गत बैठक के पश्चात नगर पंचायत गोवर्धन व फरह के ई0ओ0 को चेतावनी जारी करने के बाद भी अभी तक के जिन केंद्रों पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, संबंधित ई0ओ0 को तत्काल सिलेंडर उपलब्ध करा कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर अक्षय पात्र संस्था द्वारा हाट कुक योजना का संचालन प्रारंभ करने के संबंध में भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर पत्रावली पुनः प्रस्तुत करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को विगत छह माह में हुए प्रसव, कितने प्रसव प्राइवेट में हुए तथा कितने प्रसव सरकारी में हुए की सूचना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रसव के सापेक्ष कितने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन गया है एवं कितने बच्चों का नहीं बने हैं इसकी सूचना आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों से छह वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों की सूची भी मंगवायी गई है, जिससे यह जाँच की जा सके कि उन में से कितने बच्चों ने विद्यालय में नामांकन करा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, पेय जल एवं शौचालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित लक्ष्य 57 के सापेक्ष 39 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण हो गए हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य 80 के सापेक्ष 49 आंगनबाड़ी केंद्र पूरे हो गए हैं।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी केंद्रों का निर्माण कार्य 30 अप्रैल 2025 तक पूरा करा लिया जाए और एक माई को सभी केंद्रों का लोकार्पण माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उनके संबंध में की गई कार्रवाई निस्तारण /आख्या का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने अभी तक योगदान नहीं किया है, उनको रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे, यदि वह योगदान नहीं करते हैं तो उनका चयन निरस्त करते हुए द्वितीय बरियता वाले अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बैठक में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (मनरेगा एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निगम का चला महाबली अवैध कब्जा ध्वस्त

माफियाओं के खिलाफ रिफाइनरी थाने में दर्ज कराया मुकदमा दर्ज

उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा (डीके)। बाद गांव पर नगरनिगम ने अवैध कब्जा हटाकर माफियाओं के चंगुल से भूमि मुक्त कराई है। अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ रिफाइनरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

बाद गांव पर नगर निगम की 405 हेक्टेयर भूमि हाइवे पर स्थित है। बेशकीमती जगह देख भूमाफियाओं को लालच आ गया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीते रविवार को जगह पर कब्जा कर लिया और बाउंड्रीवाल निर्मित करा दी। नगरनिगम के अधिकारियों को पता लगते ही निगम का महाबली गरज उठा । बाउंड्रीवाल तोड़ दी। बोर्ड उखाड़ डाले।और निगम का नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। लेखपाल थान सिंह ने गांव के विक्रम सिंह, चंद्रशेखर पुत्र हर्षवरूप, केहरी पुत्र वीरेंद्र के खिलाफ अवैध कब्जे की रिपोर्ट दर्ज कराई है।थानाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया निगम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।बाद गांव निवासी एक महिला भी कब्जे के संबंध में शिकायत करने आई थी और अपनी जमीन का दावा कर रही थी जबकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जमीन वृक्षारोपण के लिए दर्ज बताई है।

-हाइवे स्थित नगर निगम की पौधारोपण की जमीन पर भू माफिया ने सीमेंट बाउंड्री वाल



लगाया है।फर्जी कागजों के आधार पर निगम की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया था पूर्व में दो पक्षों द्वारा भी तीन बार कब्जा करने की कोशिश की गई है संज्ञान में आते ही अवैध बाउंड्री पर बुलडोजर चला दिया गया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करया है।

-राकेश त्यागी सहायक नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृंदावन
-उक्त जमीन एससी कैडिडेट का पट्टा था जिसकी कई बार रजिस्ट्री भी हो चुकी है कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है ये निगम की गुंडई है।निगम की कार्रवाई गलत है। बाउंड्री तोड़ने से पहले नोटिस देना चाहिए

डूडा बनाएगा 10 सड़कें, एक करोड़ होगी अनुमानित कीमत

राजमार्ग किनारे बसी अविकसित कॉलोनियों होगा विकास

शुलभ होगा आवागमन, जल निकासी को बनेंगी नालियां

उत्तरप्रदेश की राजनीति

कोसीकलां। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) नगर पालिका परिषद क्षेत्र की राजमार्ग के किनारे बसी अविकसित नालियों सहित 10 सड़कों को दुरुस्त

कराएगा। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये होगी। विभाग को शासन ने स्वीकृति भी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू हो जाएगा। डूडा ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, पालिकाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल के अलावा विभागीय स्तर पर भी निकाय में सर्वे कराकर उन मार्गों की सूची तैयार की, जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त थे। सूची में 10 ऐसे मार्ग सामने आए जो मरम्मत योग्य मिले। इन मार्गों से जुड़ी नालियां भी क्षतिग्रस्त होने से पानी रास्तों पर बह रहा था। यहां इंटरलॉकिंग, सीसी और नाली

निर्माण के लिए एक करोड़ का प्रस्ताव तैयार हुआ। पालिकाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि डूडा को निर्माण कार्य कराने के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। परियोजना निदेशक डूडा, अजीत सिंह, ने बताया कि 10 मार्गों पर इंटरलॉकिंग, सीसी कराने व नाली निर्माण के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी है। टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। इसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद आवागमन सुलभ होगा। नालियों का निर्माण होने से रास्तों पर पानी भरने की समस्या से निजात मिलेगी।

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह

पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक -राज्य सरकार पुलिस को और अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने के लिए निरंतर उठा रही कदम -पुलिस का मूलमंत्र 'अपराध पर नियंत्रण-समाज में सुरक्षा और विश्वास' -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने की वर्दी भते एवं मेस भते में वृद्धि की घोषणा -पुलिसकर्मियों को सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सौगात



राजस्थान की राजनीति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक हैं। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान-माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को आरपीए में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पेरड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पुलिसकर्मी अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वाच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी रहती है पुलिस

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की ढाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। ये कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने सहित पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है।

पुलिस और नागरिकों के बीच होना चाहिए नियमित संवाद

शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के उपयोग से आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए।



200 करोड़ रुपये से होगा पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10 हजार पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, 5,500 नवीन पदों का सृजन किया गया है तथा इस वर्ष 3,500 नवीन पद सृजन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में एक हजार कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। साथ ही, पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं 250 लांगरी पदों का सृजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह नवाचार करती रहेगी।

350 करोड़ रुपये से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की होगी स्थापना

शर्मा ने कहा कि पुलिस मोबैलिटी के लिए लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने के लिए नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसी तरह 350 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की जाएगी। इसी तरह पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यक्षम बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने पेरड ग्राउंड में पेरड निरीक्षण किया। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कर्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही आमजन को राहत मिल रही है। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

